



## लोक उद्यम वभिग

### प्रलिमिस के लयि

लोक उद्यम वभिग, महारतन, नवरतन, मनीरतन, प्राक्कलन समति, सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यम,

### मेन्स के लयि

सार्वजनकि उद्यम वभिग के कार्य तथा इसे वतित मंत्रालय के दायरे में लाने के नियम का महत्व

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सार्वजनकि उद्यम वभिग (Department of Public Enterprises-DPE) को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुनः वतित मंत्रालय के दायरे में ला दिया है।

- वतित मंत्रालय में अब छह वभिग होंगे जबकि DPE के मूल मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनकि उद्यम मंत्रालय को अब केवल भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा।

### प्रमुख बद्दि

सार्वजनकि उद्यम वभिग के वषिय में:

- लोक उद्यम वभिग सभी केंद्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) का नोडल वभिग है और CPSEs से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है।
  - CPSEs ऐसी कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की प्रत्यक्ष हसिसेदारी 51% या उससे अधिक है।
- यह विशेष रूप से, CPSEs में नियोजित सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वतितीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्यक्रम के बारे में नीतिगत दशानियों तैयार करता है।
- इसके अलावा यह केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित बहुत से क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र करता है और उसका रखरखाव भी करता है।
  - यह अब आर्थिक मामले, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवाएँ और नियन्त्रण तथा सार्वजनकि संपत्ति प्रबंधन वभिग (Department of Investment and Public Asset Management-DIPAM) के अलावा वतित मंत्रालय में छठा वभिग होगा।
- DPE को वतित मंत्रालय में स्थानांतरित किये जाने से CPSEs के पूंजीगत व्यय, परसिंचत्ति मुद्रीकरण और वतितीय स्वास्थ्य की कुशल नियंत्रणी में मदद मिलेगी।

### पृष्ठभूमि:

- तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समति (Estimates Committee) ने अपनी रपोर्ट में, एक केंद्रीकृत समन्वय इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सार्वजनकि उद्यमों के प्रदर्शन का नियंत्रित मूल्यांकन भी कर सके।
- जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में वतित मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनकि उद्यम ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises-BPE) की स्थापना हुई।
- वर्ष 1985 में, BPE को उद्योग मंत्रालय का हसिसा बनाया गया था। मई 1990 में BPE को एक पूर्ण वभिग बनाया गया जिसे लोक उद्यम वभिग (Department of Public Enterprises- DPE) के रूप में जाना जाता है।

### प्रमुख कार्य:

- सभी लोक उद्यमों (Public Sector Enterprises- PSEs) को प्रभावित करने वाले सामान्य नीतिसंबंधी मामलों का समन्वय।
- लोक उद्यमों का पुनर्गठन करने या बंद करने तथा उनके लयि तंत्र से संबंधित सलाह देना।
- पुनरुद्धार से संबंधित सलाह देना।

- स्वैच्छकि सेवानवीत्तयोजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं उनका पुनर्वास।
- 'रत्न' का दर्जा देने सहित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का अन्य प्रकार का वर्गीकरण।
  - CPSEs को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- महारत्न, नवरत्न और मनीरत्न। वर्तमान में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मनीरत्न CPSEs हैं।

## CPSEs का वर्गीकरण

### श्रेणी

- महारत्न
- नवरत्न
- मनीरत्न

### शुरुआत

- CPSEs के लिये महारत्न योजना मई, 2010 में शुरू की गई थी, ताकि CPSEs को अपने संचालन का वसितार करने और वैश्वकि दण्डिगजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।
- नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्वकि खिलाड़ी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं।
- मनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।

### मानदंड

#### महारत्न:

- कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहयि।
- कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और वनियिक बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियमिकों के अंतर्गत नयूनतम नियंत्रित सार्वजनिक हस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहयि।
- वर्गित तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहयि।
- पछिले तीन वर्षों में औसत वार्षिक नविल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहयि।
- पछिले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहयि।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहयि।
- **उदाहरण:** भारत हेवी इलेक्ट्रोकिल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि

#### नवरत्न:

- **मनीरत्न श्रेणी - I** और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs, जिन्होंने पछिले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता जु़ापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं:
  - शुद्ध पूँजी और शुद्ध लाभ
  - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत
  - मूल्यहरास के पहले कंपनी का लाभ, वर्कग्रोप कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज
  - ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बक्सी पर लगा कर
  - प्रतिशेयर कमाई
  - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन
- **उदाहरण:** भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि

#### मनीरत्न:

- **मनीरत्न श्रेणी- 1:** मनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किंपनी ने पछिले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
  - **उदाहरण (श्रेणी- I):** भारतीय विमानपत्रन प्राधिकरण, एंट्रोकिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि
- **मनीरत्न श्रेणी- 2 :** CPSE द्वारा पछिले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी नविल संपत्ति सिकारात्मक हो, वे मनीरत्न- II का दर्जा देने के लिये पात्र हैं।
  - **उदाहरण (श्रेणी- II):** भारतीय कृष्टरमि अंग नियमाण नियम (ALIMCO ), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL), आदि
- मनीरत्न CPSE को सरकार के कसी भी ऋण पर ऋण / ब्याज भुगतान के पुनरभुगतान में चूक नहीं करनी चाहयि।
- मनीरत्न CPSE कंपनियाँ बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर नियंत्रित नहीं होंगी।

## प्राक्कलन समति

परचिय :

- इसे प्रथम बार 1920 के दशक में ब्रटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समतिविधि 1950 में स्थापित की गई थी।
- यह समतिबिजट में शामल अनुमानों की जाँच करती है तथा सार्वजनिक व्यय में 'अर्थनीति' का सुझाव देती है।
- संसद की अन्य वित्तीय समितियों में शामल हैं - लोक लेखा समति और सार्वजनिक उपकरणों की समति।

सदस्य:

- इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा ये सभी सदस्य लोकसभा से होने चाहये।
- सदस्यों को लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतनिधित्व के सदिधांतों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम स्वीकृत किया जाता है, ताकि सभी दलों को इसमें उचित प्रतनिधित्व मिल सके।
- किसी मंत्री को प्राक्कलन समितिके सदस्य/अध्यक्ष के रूप नियाचति नहीं किया जा सकता है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्यों में से की जाती है।

कार्य:

- यह समतिव्यय में मतिव्ययता और दक्षता की रपिरेट करने का प्रयास करती है।
- यह सुझाव देती है कि नीतिया प्रशासनिक ढाँचे में क्या प्रविरत्न किया जा सकते हैं तथा मतिव्ययता एवं दक्षता लाने के लिये किन वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जा सकता है।
  - इस समितिका कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान नरितर चलता रहता है तथा यह परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सदन को रपिरेट करती रहती है।
  - इसी कारण इस समितिको 'सतत् अर्थव्यवस्था समति' भी कहा जाता है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस